ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **06 November, 2020**

Shri Randeep Singh Surjewala, Gen Secretary & In-charge Communications Deptt, AICC addressed media at AICC Hdqrs., today

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा - नमस्कार दोस्तों।

आज एक पूरे देशके लिए पीड़ादायक और अत्यंत तकलीफदेह विषय लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। शहीद सैनिकों की वीरता और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है, जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और 'सक्रिय सेवा' (Active Service) के बाद उनके दूसरे करियर विकल्प पर डाका डालने की तैयारी में है। इस बारे बाकायदा 29 अक्टूबर, 2020 के पत्र से प्रस्ताव मांगा गया है, जिसकी कॉपी संलग्नक A1 है।

एक तरफ तो स्वांग रच प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों के जीवन में उनकी पेंशन काट अंधेरा फैलाने का दुस्साहस कर रहे हैं। यही भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद है।

1. सेना में भर्ती यानि 'सैन्य कमीशन' के समय 'इंडियन मिलिटरी एकेडमी' में हर अधिकारी से 20 साल का अनिवार्य सर्विस बॉन्ड भरवाया जाता है। 20 साल की सेवा के बाद सैन्य अफसर 'Last Drawn Salary' यानि 20 साल की सेवा पूरी होने पर जो मूल तनख्वाह मिल रही हो, उसकी 50 प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार है। परंतु मोदी सरकार का ताजा सेना विरोधी प्रस्ताव (संलग्नक A1) उस 50 प्रतिशत पेंशन को भी आधी कर देने का है। उदाहरण के तौर पर यदि 20 साल की सेवा उपरांत किसी सैन्य अधिकारी को आखिरी मूल तनख्वाह 1,00,000 रु. प्रति माह थी, तो पिछले 73 वर्षों से उसकी पेंशन 50,000 रु. प्रति माह मिलनी सुनिश्चित है, यानि आखिरी मूल तनख्वाह का 50 प्रतिशत। पर मोदी सरकार का नया प्रस्ताव अब सैन्य अधिकारी की पेंशन 50,000 रु. प्रतिमाह से घटाकर 25,000रु. प्रतिमाह कर देगा। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करने वाले अधिकारियों की आधी पेंशन काटने की ऐसी निर्मम और निर्दयी प्रस्तावना केवल सेना विरोधी मोदी सरकार ही कर सकती है।

2. सेना में भर्ती हुए 100 अफसरों में से औसतन 65 प्रतिशत सैन्य अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही सीमित रह जाते हैं। केवल 35 प्रतिशत अधिकारी ही कर्नल या उससे ऊपर के पदों पर जा पाते हैं। ऐसे में 20 साल सेवाएं देने के बाद वो सैन्य अधिकारी पूरी पेंशन के साथ जिंदगी में एक दूसरा करियर विकल्प तलाश कर लेते हैं तथा प्रभावी तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान

देते हैं। सेना को इसका सीधा फायदा यह है कि फौज सदा युवा बनी रहती है, जिसे मिलिटरी की भाषा में 'Lean & Mean Fighting Force' कहा जाता है। अगर मोदी सरकार की प्रस्तावना लागू हो जाएगी, तो सदा के लिए 65 प्रतिशत सैन्य अफसरों का दूसरा करियर विकल्प भी खत्म हो जाएगा और सेना से बाहर सिविलियन क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में उनका रचनात्मक सहयोग भी।

3. मोदी सरकार की नई प्रस्तावना के मुताबिक केवल उस सैन्य अफसर को पूरी पेंशन मिलेगी, जिसने 35 साल से अधिक सेना की सेवा में बिताए हों। परंतु सेना के 90 प्रतिशत अफसर तो 35 साल की सेवा से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार 90 प्रतिशत सेना के अफसरों को पूरी पेंशन से वंचित करने का षडयंत्र कर रही है।

4. सैन्य अफसरों की सेवाओं की शर्तों को भी 'Back Date' से संशोधित नहीं किया जा सकता। जब सेना में भर्ती होते हुए 20 साल की अनिवार्य सेवा और 20 साल के बाद फुल पेंशन पर रिटायरमेंट की शर्त रखी गई है, तो आज मोदी सरकार उन सारी सेवा शर्तों को कैसे संशोधित कर सकती है? इससे सैन्य अधिकारियों का मनोबल टूटेगा।

5. भारत की तीनों सेनाओं में पहले से ही 9,427 अफसरों की कमी है। जून, 2019 के आंकड़े बताते हैं कि थल सेना में 7,399, नौसेना में 1,545 और वायु सेना में 483 अफसर कम हैं। मोदी सरकार की सेना का मनोबल तोड़ने वाली इस प्रस्तावना से देश के युवाओं का सेना में भर्ती होने के प्रति आकर्षण घटेगा तथा आखिर में देश का नुकसान होगा।

सच्चाई यह है कि मोदी सरकार लगातार सेना विरोधी कार्य कर रही है:-

1. मोदी सरकार ने आज तक 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) लागू नहीं की।

2. मोदी सरकार ने सेना की 'नॉन फंक्शनल यूटिलिटी बेनेफिट स्कीम' खत्म कर दी, जिसे कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था ताकि ऑटोमैटिक टाईम बाउंड पे प्रमोशन हो सकें।

3. यहां तक कि मोदी सरकार ने सेना की कैंटीन (CSD) से सैनिकों द्वारा इस्तेमाल के लिए खरीदे जाने वाले सामान की मात्रा पर भी सीमा लगा दी। चार साल अदालती मुकदमों के बाद ही यह निर्णय वापस हो पाया।

4. मोदी सरकार ने सियाचिन और लद्दाख में सैनिकों के लिए खरीदे जाने वाले सर्दी के ईक्विपमेंट, जूते, बुलेटप्रूफ जैकेट की खरीद में भयंकर देरी की।

5. मोदी सरकार ने 'डिसएबिलिटी पेंशन' पाने वाले सेना के अधिकारियों तथा सैनिकों पर टैक्स लगा दिया।

6. मोदी सरकार ने 'Short Service Commission' पर देश सेवा करने वाले अधिकारियों और सैनिकों की मेडिकल सुविधा खत्म कर दी।

7. यहां तक कि 70,000 सैनिकों वाली माउंटेन कोर, जो चीन की सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात की जानी थी, का गठन भी मोदी सरकार ने पैसे की कमी बताकर खारिज कर दिया।

और अब सेना पर मोदी सरकार के ताजे हमले की इस प्रस्तावना ने झूठे राष्ट्रवादियों का सेना विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है।

Shri Randeep Singh Surjewala said- Modi Govt has betrayed our brave Armed Forces. Modi Govt is hurting the morale of our Army Officers by snatching away their pension.

Habitual of seeking votes on the sacrifice of our brave soldiers and on Nationalism, Modi Govt has become the first regime in history to 'Steal the Pension' and alternate career choice after 'Active Service' of those officers who protect our motherland. A letter circulated by the Department of Military Affairs (DMA) in the office of the CDS [**Annexure A1**] has sought suggestions for the same.

This Diwali, PM Modi exhorted the nation to light a *diya* for our soldiers, but has ensured darkness in their lives by attempting to reduce their pension by half.

This is BJP's Fake Nationalism!

1. At the time of recruitment in the Army i.e. 'Military Commission', every officer in the 'Indian Military Academy' has to compulsorily sign a 20-year mandatory service bond. **An officer after 20 years of rigorous service, presently gets 50% of their last drawn salary as pension, but Modi Govt's new proposal is snatching away 50% of that** [**Annexure A1**] For instance, if an officer gets Rs 1 lakh as their last drawn salary. Presently he will get Rs 50,000 as pension. But BJP's new proposal shall only give the officer Rs 25,000 ! **Only an Anti-Army Modi Govt can indulge in such ruthless brazenness to deduct half the pension of the officers serving the country and insult their valour and sacrifice.**

2. On an average 65% i.e. 65 of the 100 army officers admitted to the Army are confined to the rank of Lieutenant Colonel. Only 35% officers can aspire to reach to the position of Colonel or above. In such a situation, after serving for 20 years, those military officers find a second career option in life with full pension and effectively contribute to the nation building. Thereby, the

Indian Army always remains young, which in military language is called 'Lean & Mean Fighting Force'. **If the Modi Govt's devious proposal comes into force, then 65% of military officers will forever lose their second career option and their creative support in nation building in civilian areas outside the military.**

3. According to Modi Govt's new proposal only those officers who have spent more than 35 years in the Armed Forces service shall be entitled to a 'Full Pension'. But reality is 90% of the Army officers retire before 35 years of service**. In such a situation, the Modi Govt is hatching a conspiracy to deny 90% of Army officers their full pensions.**

4. **The terms of service of military officers also cannot be modified with 'Back Date'.** When 20 years of compulsory service and full pension after 20 years has been prescribed for retirement, then how can the Modi Govt revise all those conditions of service? **This will only lower the morale of our Armed Forces.**

5. There is already a shortage of 9,427 officers in all the three Armed services of India. The figures available for June 2019 show that **there are 7,399 less officers in the Army, 1,545 are wanting in the Navy and 483 less in the Air Force. Modi Govt's agenda driven proposal which breaks the morale of the Indian Army shall reduce, make our Armed Forces less attractive for our youth** to join in and ultimately the country will suffer loss.

Modi Govt is a habitual offender in insulting the Armed Forces by 'back door' cuts in spending.

- Modi Govt did not implement '**One Rank, One Pension**'(OROP)
- Modi Govt withdrew the much deserved **'Non Functional Utility' (NFU) benefits**, a scheme brought by the Congress-UPA in 2008 to ensure automatic time bound pay promotion.
- Modi Govt imposed monthly limits on the quantity of items that can be purchased by individuals from **Canteen Stores Department (CSD)** outlets, that caters to serving and retired personnel. It took four years and a court case to reverse the order.

- Modi Govt delayed **the procurement of winter gear, shoes, bullet proof jackets for our Jawans posted in Siachen and Ladakh. (**CAG observation).

- Modiv Govt decided to **tax Armed Forces personnel who get 'disability pension' on 'account of injuries suffered in the course of service'** at the time of their superannuation or premature retirement.

- Modi Govt withdrew the medical benefits/pensions to our Jawans who have valiantly served the Nation under **Short Service Commission.**

- Modi Govt even shelved a special regiment called **'Mountain Strike Corps**' along the China border with 70,000 additional soldiers, citing lack of money.

And now, Modi Govt's fresh attack on the Indian Army has exposed the anti-Army face of the Fake Nationalists!

'वन रैंक, वन पैंशन' के संदर्भ में पूछे एक प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि आदरणीय साथी 2014 में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार ने राहुल गांधी जी की प्रार्थना और फौज के, जो हमारे परसोनेल हैं, वैटरन हैं, उनकी दरख्वास्त पर जो आदेश जारी किया था, वो 'वन रैंक, वन पैंशन' का फाइनल ऑर्डर था। मोदी सरकार ने निर्दयता से देश की फौज से, देश के सैनिकों से जन रणबांकुरों की कुर्बानी पर वो राजनीति करते हैं, उनसे 'वन रैंक, वन पैंशन' का अधिकार छीन लिया। अनेकों बार श्री राहुल गांधी ने कहा है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है, इसी मंच से कहा है, हम वन रैंक, वन पैंशन के पक्षधर हैं। जो अभी मोदी जी दे रहे हैं, वो वन रैंक, फाइव पेंशन्स हैं। तो सेम रैंक में पांच अलग-अलग तरह की पैंशन मिल रही है। ये घोर अन्याय देश की फौज के साथ है और मैंने इसलिए 7 अलग-अलग पहलू गिनाए।

6 साल से लगातार सेना के इंट्रेस्ट पर मोदी जी हमला कर रहे हैं और सेना की कुर्बानी पर राजनीति, इसलिए इससे ज्यादा निंदाजनक कार्य कोई हो ही नहीं सकता।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि आदरणीय साथी, पूरा देश समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारी सेना के साथ एकजुट खड़ा है। हमें हमारी सेना पर गर्व है कि इस विषम परिस्थितियों में भयंकर बर्फबारी के बीच मोदी जी ने सेना को पूरा प्रोटैक्टिव गियर भी नहीं दिया बर्फ से बचने के लिए, उसके बावजूद भी भारत माता का झंडा पकड़, देश का तिरंगा पकड़ हमारी सेना के बहादुर जवान और अधिकारी आज भी दुश्मन के सामने भारत मां की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े हैं, हर कुर्बानी को तैयार। हमें गर्व है उन रणबांकुरों पर। पर सवाल ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार क्या कर रही है, वो चीनी दुस्साहस का कैसे जवाब देगी? चीन को भारतीय सीमा से पीछे कैसे खदेड़ेगी, क्योंकि दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री तो चीन शब्द बोलने से

डरते हैं। चीन का शब्द ही उनके मुंह से निकलता नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब, देश के प्रधानमंत्री को 130 करोड़ देशवासियों को देना चाहिए।

पिछले तीन दिनों में हरियाणा में जहरीली शराब से 40 लोगों की मृत्यु होने से संबंधित पूछे एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में शराब माफिया, नाजायज़ शराब बनाने और बेचने का धंधा खट्टर सरकार की नाक के नीचे चल रहा है और खट्टर सरकार सोई पड़ी है। हमने देखा कि लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान करोड़ों बोतलें शराब का हेरफेर हुआ। हमने जांच की मांग की, जांच की रिपोर्ट को दबा दिया गया, कोई एफआईआर नहीं हुई और अब सोनीपत-पानीपत जिलों में तीन दिन में 40 लोग मर गए, ज़हरीली शराब पीकर। क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला, जो इस विभाग के मंत्री हैं, सब लोगों को ज़हरीली शराब की भट्टी में झोंकना चाहते हैं? कब पकड़े जाएंगे दोषी और कब नाजायज़ शराब का धंधा रुकेगा? ऐसी सरकार को और ऐसे मंत्री को एक क्षण के लिए भी, जिसके महकमें में नाक के नीचे 40 लोग मर जाएं, सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC

Ministry of Defence
Office of the Secy DMA

Subject: ***Review of Retirement Age of Service personnel***

1. The proposal for increase in ages of retirement is presently under consideration. Based on the feedback from the environment, and the deliberations/presentations on the subject, it is directed that a draft GSL (in two parts) be processed for changes in retirement profile and pension entitlements as enumerated in succeeding paragraphs.

2. **Increase in ages of retirement**. (less AMC and MNS):-

(a) **Officers**.

(aa) **Upto Colonels** and eqvt – **57** years

(ab) **Brigadiers** and eqvt – **58** years

(ac) **Maj Gen** and eqvt – **59** years

(ad) **Lt Gen** onwards – **No change**

(b) **JCO/OR/equivalent in the *IN* and IAF**. 57 years for all personnel in Logistics, Technical and Medical Branch (Includes EME, ASC and AOC for Army).

3. **Pension entitlements for Pre Mature Release (PMR)**. There are a large number of personnel who are boarded out in view of lesser vacancies and some service restrictions. At the same time there are several specialists/super-specialists who are trained for high skill jobs in the services that leave the service to work in other sectors. Such loss of high skilled manpower, results in void in the Services skill matrix and is counter-productive to the Armed Forces. In view of this, it has been decided to review the Pension entitlements as under:-

(a) Pension entitlements for the PMR of personnel will be as under:-

(i) **20-25** years service - **50%** of entitled pension.

(ii) **26-30** years service - **60%** of entitled pension.

(iii) **31-35** years service - **75%** of entitled pension.

(iv) **Above 35** years service - full pension.

(b) There will be no change of pension entitlements of Battle Casualties.

4. It is requested that the draft GSL may kindly be processed for the perusal of Secy DMA by **10 Nov 2020**.

(Robin Chakravorty)
Captain (IN)
Dy DA to CDS
Tele No. 011-23794144

SO to AS (TS)

Reference No. [illegible] Agenda/2020/DMA Sectt dated 29 Oct 2020

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA